

MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (DR. U.
VENKATESWARLU): I lay on the
Table, a copy each (in English and
Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts
of the National Institute of
Urban Affairs, New Delhi for
the year 1995-96, together
with the Auditors' Report on
the Accounts.
- (b) Statement by Government
accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for
the delay in laying the
papers mentioned at (a)
above.

[Placed in Library. See No. LT-1379/97].

- (ii) Memorandum of Understanding
between the Government of
India (Ministry of Urban Affairs
and Employment) and National
Buildings Construction
Corporation Limited, for the
year 1996-97.

[Placed in Library. See No. LT-1378/97].

NOMINATION OF PANEL OF VICE- CHAIRMAN

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have
to inform Members that Hon. Chairman
has nominated Mr. V. Narayanasamy and
Mr. Ajit P.K. Jogi to function as Vice-
Chairman during the current session of
the Rajya Sabha.

RE. DISCRETIONARY QUOTA OF MEMBERS OF PARLIAMENT FOR TELEPHONE AND GAS CONNEC- TIONS

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति
महोदया ...

उपसभापति: आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: महोदया, सैंकड़ों का
गैस और टेलीफोन का कोटा खल कर दिया गया है।

उपसभापति: यहां नहीं लिखा है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: महोदया, यह तो खल
हुआ है फंक्त हमें इनफॉर्मेशन नहीं है कि क्या मिनिस्टर
का कोटा भी खल हुआ है या नहीं हुआ है? सेक्रेटरी
का कोटा खल हुआ है या नहीं हुआ है और ये जं
ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी तो गैस अं
टेलीफोन के कनेक्शन दे रहे हैं। मैम्बर्स का कोटा खल
कर दें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मिनिस्टर
सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेट्स का कोटा खल किया गया है या
नहीं? मैम्बर्स का तो गैस और टेलीफोन का कोटा खल
कर दिया गया है, ऐसा स्पीकर साहब ने लोक सभा में
घोषित किया है। मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ

SHRIMATI RENUKA CHOW
DHURY (Andhra Pradesh): They take
away Members' privilege and the officials
have unlimited privilege.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: आप इसको मिनिस्टर
से शुरू करिए और सेक्रेटरीज से शुरू करिए। मैंने
देखा है कि सेक्रेटरीज सैंकड़ों की तादाद में ये कनेक्शन
देते हैं, मामूली से मामूली अफसर कनेक्शन दे रहे हैं।
उनको परमीशन है पर सिर्फ मैम्बर्स का डिस्क्रिमिनेशन
कोटा खल करना ठीक नहीं है। उनका कोटा खल कर
भी शुरू करिए और यहां हाऊस में बताइए कि इस
बाद यह कोटा न कोई मिनिस्टर यूज करेगा, न कोई अं
करेगा। सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही
कनेक्शन दिए जाएंगे।

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Madam, there is one more point
to be considered by you and the whole
House. A unilateral announcement has
been made in the Lok Sabha. It
is not applicable to the Members of the Rajya
Sabha?

THE DEPUTY CHAIRMAN: That
is not the point.

SHRI SATISH AGARWAL: The
issue should be some consultation between the
Rajya Sabha and the Lok Sabha and with
our hon. Chairman and our hon. leader
as well. It has been suddenly announced
but is it applicable to the Members of the
Rajya Sabha? If it is, since when will
be applicable—April or July?